समृद्ध किसान सशक्त मध्यप्रदेश

वैश्विक मंच पर पहचान बनाने की तैयारी... राज्य सरकार के प्रयास और आधुनिक तकनीक के साथ बदल रही है उद्यानिकी और पुष्प उत्पादन क्षेत्र की तस्वीर

स्वाद और गुणवत्ता के दम पर एमपी की 12 उद्यानिकी फसलों को मिला जीआई टैग

लहसुन, संतरा, टमाटर व धनिया उत्पादन में हम पूरे देश में प्रथम

भोपाल

मध्यप्रदेश ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक उद्यानिकी और पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में देश में एक विशिष्ट और बेजोड़ पहचान स्थापित की है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों और नीतिगत प्रोत्साहनों के चलते पिछले दो वर्षों में उद्यानिकी का रकबा 25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 29 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस अभूतपूर्व छलांग के साथ ही कुल उद्यानिकी उत्पादन भी 389 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 438 लाख मीट्रिक टन से अधिक दर्ज किया गया है। इस सफलता को वैश्विक स्तर पर तब बड़ी मान्यता मिली, जब प्रदेश की 12 प्रमुख उद्यानिकी फसलों को एक साथ प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ।

एमपी अभी संतरा, टमाटर, धनिया और लहसुन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, सीताफल, बंदगोभी, प्याज और हरी मटर के उत्पादन में दूसरे व नींबू, पतागोभी, लाल मिर्च एवं खरबूजा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।

फ्लोरीकल्चर में भी मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर

फूलों की खेती (फ्लोरीकल्चर) में भी राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जहां करीब 45 हजार हेक्टेयर भूमि पर गुलाब, जरबेरा, गेंदा, सेवंती, रजनीगंधा और ग्लेडियोलस जैसे व्यावसायिक फूलों की खेती की जा रही है। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, सतना, छिंदवाड़ा, गुना और जबलपुर पुष्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं।

अब हॉर्टीकल्चर का रकबा भी 30 लाख हेक्टयर पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

सरकार ने आगामी वर्षों में उद्यानिकी के रकबे को 30 लाख हेक्टेयर और कुल उत्पादन को 490 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए इजरायल के तकनीकी सहयोग से फूलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु एक अत्याधुनिक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किया जा रहा है। साथ ही, फलों और सब्जियों के स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन के लिए प्रदेश में लगभग 10 हजार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिससे 1 लाख से अधिक किसानों, युवाओं और उद्यमियों को कृषि उद्यमिता का वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर लाभांवित किया जाएगा।

अन्नदाता की मेहनत को सम्मान... केंद्र सरकार के तय लक्ष्य से ज्यादा गेहूं खरीद कर बनाया नया रिकॉर्ड

बोनस के साथ इस बार 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद, यह बीते साल से 33% ज्यादा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दताना के नागझिरी स्थित अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र के औचक निरीक्षण में मंडी में लाए गेहूं का अवलोकन किया।

भोपाल

मध्यप्रदेश के परिश्रमी किसानों और सरकार की सुदृढ़ नीतियों के साझा प्रयासों से राज्य ने गेहूं खरीदी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। खरीद सत्र के दौरान राज्य सरकार ने 40 प्रति क्विंटल बोनस के साथ 2,665 प्रति क्विंटल की प्रभावी दर से कुल 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड उपार्जन किया है। यह बीते वर्ष के लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से करीब 33.33 फीसदी ज्यादा है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस बार मध्यप्रदेश के लिए 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया था। इसके मुकाबले राज्य ने 104 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भंडार में अपना ऐतिहासिक योगदान दिया है। सरकार ने आगामी समय में गेहूं की प्रति क्विंटल कीमत को 2700 रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।

किसान हित में तीन महत्वपूर्ण फैसले... जिनसे बना नया रिकॉर्ड

1. मौसम की बेरुखी से प्रभावित किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने 50% तक खराब चमक) वाले गेहूं की भी पूरी कीमत पर खरीदी सुनिश्चित की।
2. इस वर्ष कुल 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जहां किसानों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई।
3. गेहूं खरीद से जुड़ी हर जानकारी के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए।

लघु-सीमांत किसानों को प्राथमिकता, स्लॉट बुकिंग में दिखी संवेदनशीलता

प्रदेश के 13 लाख 46 हजार से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस का सीधा लाभ मिला है। इसमें छोटे, लघु एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कुल 34 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का विशेष अवसर दिया गया। किसानों की व्यावहारिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए स्लॉट बुकिंग की तारीखों को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई तक किया गया था। साथ ही, शनिवार के दिन भी स्लॉट बुकिंग व उपार्जन जारी रखा गया।

धान उत्पादकों को ₹ 22,202 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

धान उपार्जन में भी राज्य ने नए आयाम छुए हैं। पिछले दो वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश के 14 लाख 31 हजार से अधिक धान उत्पादक किसानों से 95 लाख 27 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान का सफल उपार्जन किया गया है, जिसके एवज में 22,202 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई है। इसके अतिरिक्त, 'मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना' के तहत प्रदेश के समस्त धान उत्पादकों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

यहां भी हमारा दबदबा

- **मक्का उत्पादन में प्रथमः** अनाज श्रेणियों में बेहतर प्रबंधन और उन्नत बीजों के दम पर मध्यप्रदेश देश में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है।
- **जैविक कपासः** पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों के सफल क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश जैविक कपास के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है।

रानी दुर्गावती प्रोत्साहन... वैश्विक बाजारों तक पहुंच आसान

हमारे श्रीअन्न को नया जीवन, किसानों को 1000 रु. प्रति क्विंटल का बोनस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल के कुकरू में खेत में हल के साथ बुवाई की।

भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत ऐतिहासिक काम कर रही है। इसमें पारंपरिक मोटे अनाजों (मिलेट्स) को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है। इससे जनजातीय क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। राज्य सरकार ने कोदो और कुटकी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 1000 रुपये प्रति क्विंटल का सीधा नकद बोनस देने का क्रांतिकारी फैसला लागू किया है। खरीफ सीजन के दौरान रिकॉर्ड 15,000 मीट्रिक टन कोदो-कुटकी की खरीदी की गई है। सरकार ने बाजार में कुटकी का 3500 और कोदो का 2500 रुपये प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड दर पर उपार्जन पक्का किया है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 15 प्रमुख श्रीअन्न उत्पादक जिलों के लगभग 4,000 किसानों से 3,000 मीट्रिक टन से अधिक कोदो-कुटकी की विशेष खरीदी पूरी कर ली गई है। यह वजह है कि पारंपरिक मोटे अनाजों को सुपरफूड बनाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा मप्र को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन का अवार्ड दिया गया है

3,941 किसानों के खातों में ₹2.84 करोड़ का बोनस ट्रांसफर

योजना के तहत त्वरित तौर पर 3,941 श्रीअन्न उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 2 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि सीधे बोनस के रूप में भेजी जा चुकी है। श्रीअन्न को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयासों के तहत ही प्रदेश की 'सिताही कुटकी', 'नागदमन कुटकी', 'बैगानी अरहर' और 'छत्रिय धान' को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ है।

आगामी वर्ष के लिए 40 हजार मीट्रिक टन का नया लक्ष्य

इस सफलता से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कोदो-कुटकी उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाकर 40 हजार मीट्रिक टन तय किया है। सरकार के इस बड़े कदम से प्रदेश के सुदूर व जनजातीय क्षेत्रों के छोटे और सीमांत किसानों की आय में भारी वृद्धि होना पूरी तरह तय है।

मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना...

एग्री-बिजनेस के लिए युवाओं को मिलेगी ₹2 करोड़ तक वित्तीय मदद

योजना का मुख्य उद्देश्य युवा जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाना है

भोपाल

मध्यप्रदेश के ग्रामीण युवाओं और किसानों के बच्चों को कृषि क्षेत्र में ही बेहतरीन स्वरोजगार तथा नए स्टार्टअप के अवसर देने के लिए 'मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना' को एक नए और प्रभावी रूप में धरातल पर उतारा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं को 'जॉब सीकर' (नौकरी तलाशने वाले) के बजाय 'जॉब क्रिएटर' (रोजगार देने वाला) बनाना है। योजना के तहत पात्र युवाओं को कृषि आधारित उद्योग, एग्री-बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग-पैकिंग सेंटर और बड़ी खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) इकाइयां स्थापित करने के लिए ₹2 करोड़ तक की भारी परियोजना वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत पर आकर्षक ऋण सब्सिडी और ब्याज अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे शुरुआती लागत का आर्थिक बोझ बेहद कम हो जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल स्थानीय कृषि उपज का वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन) हो रहा है, बल्कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्थानीय युवाओं के लिए नियमित और सम्मानजनक रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं।

फसल बीमा में किसानों को राहत; बीमित राशि बढ़ी

भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस बार धान में 4100, मक्का में 2350 और सोयाबीन में 3910 रुपये प्रति हेक्टेयर तक बीमित राशि में इजाफा हुआ है। यदि फसल को नुकसान होता है, तो धान में 10%, मक्का में 7% और सोयाबीन में 5% तक क्लेम राशि बढ़कर मिलने की राह आसान हुई है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई अधिसूचित है।

उदाहरण के तौर पर, शिवपुरी में धान की बीमित राशि 40,700 से बढ़ाकर 44,800 रुपये, छतरपुर में सोयाबीन की बीमित राश 39,590 से बढ़ाकर 43,500 रुपये और बड़वानी में मक्का की राशि 31,760 से बढ़ाकर 34,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे आनुपातिक रूप से मिलने वाली क्लेम राशि में किसानों को सीधा लाभ प्राप्त होगा।

आयातित तुअर पर मंडी टैक्स माफ, तिलहन पर भी सरकार का फोकस

दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मिशन पर मध्यप्रदेश, खर्च होंगे 123 करोड़ रुपए

भोपाल । देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य में अहम योगदान देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के लिए महत्वाकांक्षी दाल मिशन को वित्तीय मंजूरी दे दी है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर की खेती का रकबा बढ़ाना है। किसानों को जलवायु अनुकूल उन्नत बीज दिए जाएंगे। साथ ही, स्टोरेज के आधुनिक इंतजाम किए जाएंगे। इस योजना के लिए ₹123.82 करोड़ की कार्ययोजना को वित्तीय स्वीकृति मिली है।

बता दें कि सरकार ने आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया है। उड़द, चना और मसूर की शत-प्रतिशत खरीदी की जा रही है। रबी सीजन में 91 हजार से अधिक किसानों से 2.71 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा गया है। वहीं, 76 हजार से अधिक किसानों से 1.85 लाख मीट्रिक टन मसूर का सफल उपार्जन हुआ है। इसके साथ ही उड़द की खरीदी पर ₹600 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। इसके चलते, मध्यप्रदेश 20.4% हिस्सेदारी के साथ देश में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य बना हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर के मल्हारगढ़ में सिंगल क्लिक से सोयाबीन भावांतर राशि का अंतरण किया।

1.50 लाख: भावांतर योजना से सोयाबीन और सरसों के किसानों को संबल

बाजार में फसलों के दामों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू है। इसके तहत 7.10 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खातों में ₹1,475 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। अब सरसों और धान को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। योजना के तहत अब तक 1.50 लाख से अधिक सरसों उत्पादक किसान पंजीयन करा चुके हैं।

गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य और नई शुगर फैक्ट्री की सौगात

भोपाल। केंद्र सरकार ने गन्ना उत्पादकों के हित में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला लिया है। सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस निर्णय से मध्यप्रदेश के गन्ना किसानों को सीधा और बड़ा आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश के कोलारस में एक नई आधुनिक शुगर फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। इस शुगर मिल के शुरू होने के बाद क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें स्थानीय स्तर पर ही एक बड़ा, व्यवस्थित और सुविधाजनक बाजार उपलब्ध होगा, जिससे परिवहन की कठिनाइयों में कमी आएगी और विपणन की प्रक्रिया भी अधिक सुगम बन सकेगी।

नवाचार से महकी खेती... पारंपरिक खेती की रूढ़ियों को तोड़कर धार जिले के दो किसानों ने पेश की कामयाबी की नई मिसाल

धार के सुखदेव ने शेडनेट हाउस में फसल उगाकर 3 महीने में कमाया 3 लाख मुनाफा, ड्रिप तकनीक से सिंचाई कर नरेंद्र को 2 लाख की लागत पर 6 लाख का फायदा

संरक्षित खेती अपनाकर सरकारी योजनाओं के सहारे मिली सफलता

भोपाल

कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और सोच आधुनिक, तो माटी भी सोना उगलने लगती है। धार जिले के दो प्रगतिशील किसानों ने अपनी मेहनत और आधुनिक तकनीक के संगम से इस बात को सच कर दिखाया है। इन्होंने खेती को केवल आजीविका का साधन नहीं माना, बल्कि नए दौर की तकनीकों को अपनाकर मुनाफे का रास्ता तैयार किया है। इनमें से एक हैं सुखदेव और दूसरे हैं नरेंद्र...जिन्होंने पुरातन तरीके से चली आ खेती की परंपराओं को तोड़ा ही नहीं, बल्कि अपने हौंसले से लाखों किसानों को नया रास्ता भी दिखाया है।

तकनीक का फायदा: संरक्षित खेती और ड्रिप इरीगेशन से पारंपरिक की तुलना में 3 से 4 गुना मुनाफा

सुखदेव की मेहनत ने लिखी कामयाबी की नई कहानी

धार जिले के निसरपुर विकासखंड के ग्राम निम्बोल निवासी सुखदेव (पिता टीकम पाटीदार) के पास 1.565 हेक्टेयर कृषि भूमि है। वे बरसों से पारंपरिक खेती कर रहे थे, जहां प्रति एकड़ बमुश्किल 50 हजार रुपये का लाभ मिल पाता था। सुखदेव ने उद्यानिकी विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का लाभ उठाया और अपने खेत के 4000 वर्गमीटर हिस्से में एक आधुनिक शेडनेट हाउस का निर्माण करवाया। इस काम के लिए विभाग की तरफ से उन्हें 1.42 लाख रुपये का शासकीय अनुदान मिला। सुखदेव

ने इसमें खीरे की व्यावसायिक किस्म की बुवाई की। बीज, खाद, दवाई और मजदूरी को मिलाकर उनका कुल खर्च 2 लाख रुपये आया। लेकिन जब 3 महीने बाद फसल तैयार हुई, तो सुखदेव ने तमाम खर्चे काटकर मात्र 3 महीने के भीतर 3 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

पानी की हर बूंद के सही उपयोग से बदली तकदीर

कामयाबी की ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी निसरपुर के ही एक और कृषक नरेंद्र (पिता धुरजी पाटीदार) ने लिखी है। नरेंद्र के पास 2.000 हेक्टेयर का रकबा है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अपने पूरे खेत में आधुनिक ड्रिप इरीगेशन (टपक सिंचाई) प्रणाली को स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने तरबूज की उन्नत खेती की शुरुआत की। नरेंद्र ने फसल में 2 लाख रुपये की लागत लगाई। ड्रिप तकनीक के साथ मल्चिंग शीट का उपयोग करने से खेत में पानी की एक-एक बूंद का सही उपयोग हुआ,

जिससे खाद, पानी, समय और मजदूरी की भारी बचत हुई। जब फसल बाजार में पहुंची, तो नरेंद्र को 2 लाख की लागत के मुकाबले 6 लाख रुपये की शुद्ध बचत प्राप्त हुई। नरेंद्र की यह सफलता साबित करती है कि अगर पानी का सही प्रबंधन हो तो कम लागत में भी रिकॉर्ड मुनाफा कमाया जा सकता है।

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और फसल बीमा में एमपी को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार

भोपाल | मध्यप्रदेश ने कृषि क्षेत्र के बेहतर बुनियादी ढांचे और योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ और विवादमुक्त क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2026 में मध्यप्रदेश की एस.एल.बी.सी. को देश में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सर्वश्रेष्ठ और देश में सर्वाधिक उपयोग के लिए मध्यप्रदेश को लगातार तीन वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) पुरस्कार में भी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में मध्यप्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

D-11081/26